

वशिव वन लक्ष्यों को हासलि करने की राह पर नहीं

प्रलिमिस के लयि:

पेरसि समझौता, वन, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस, पार्टियों का सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (COP 26), राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारलि योगदान (NDC)

मेन्स के लयि:

पेरसि जलवायु समझौता और इसके प्रभाव ।

चर्चा में क्यों?

एक नई रपिर्ट के अनुसार, दुनयिा वर्ष 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और पूर्व स्थति को प्राप्त करने संबंधी वन लक्ष्यों को हासलि करने की राह पर नहीं है ।

- **पेरसि समझौते** के तहत ग्लोबल वार्मगि को 1.5 डगिरी सेल्सयिस तक सीमति करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वनों की कटाई को रोकना आवश्यक है ।

प्रमुख बडि:

- उत्सर्जन में कटौती के लयि आवश्यक प्रतबिद्धताओं का केवल 24% ही अब तक पूरा कयिा गया है ।
- वन आधारलि कार्य पेरसि समझौते की महत्तवाकांक्षाओं को पूरा करने में एक आवश्यक योगदान दे सकते हैं । यह जलवायु आपदा को रोकने में मदद करने के लयि लगभग 27% समाधान प्रदान कर सकता है ।
- वन आधारलि समाधान वर्ष 2030 तक लगभग 4 गीगटन की एक महत्त्वपूर्ण वार्षकि शमन क्षमता प्रदान करते हैं
- स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय इन परिणामों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमकि नभिते हैं ।
- हाई फारेस्ट लो डफिरिस्टेशन (HFLD) देश दुनयिा भर में उष्णकटबिंधीय वन कार्बन का 18% संग्रहीत करते हैं और पर्याप्त जलवायु वतित तक उनकी पहुँच में तेज़ी से सुधार कयिा जाना चाहयि ।
- लेकिन वर्तमान वन जलवायु वतित तंत्र उनके ऐतिहासकि संरक्षण को पुरस्कृत करने और वनों की कटाई के बढ़ते दबावों का वरिध करने के लयि पर्याप्त नहीं है ।

रपिर्ट में दयि गए सुझाव:

- मौजूदा प्रतबिद्धताओं को वास्तवकिता में परिवर्तित कयिा जाना चाहयि और वनों के वतितपोषण के लयि तत्काल नई प्रतबिद्धताएँ की जानी चाहयि ।
- इनमें से केवल आधी प्रतबिद्धताओं को 'उत्सर्जन में कमी खरीद समझौतों' के माध्यम से प्राप्त कयिा गया है । इन प्रतबिद्धताओं के लयि धन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है ।
- महत्तवाकांक्षी वन-आधारलि जलवायु समाधानों को वकिसति करने और कार्यान्वति करने के लयि देशों को अपने कार्यों को बढ़ाने हेतु वतितयि सहायता प्रदान की जानी चाहयि ।
- वनों की रक्षा, स्थायी प्रबंधन और पुनरस्थापना के लयि प्रभावी कार्य लागत जलवायु परिवर्तन शमन प्रदान कर सकते हैं । ये क्रयिाएँ जैवविविधता में गरिावट को भी कम कर सकती हैं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रतलिचीलापन बढ़ा सकती हैं ।
- वर्ष 2030 के लक्ष्यों को पहुँच के भीतर बनाए रखने के लयि वर्ष 2025 के बाद से प्रत्येक वर्ष उत्सर्जन में कमी की जानी चाहयि ।

पेरसि समझौता:

- **परचिय:**
 - पेरसि समझौते (जसि कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज़-21 या COP-21 के रूप में भी जाना जाता है) को वर्ष 2015 में अपनाया गया था ।

- इसने **क्योटो प्रोटोकॉल** का स्थान लिया जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये पूर्व में किया गया समझौता था।
- पेरिस समझौता एक वैश्विक संधि है जिसमें **लगभग 200 देश, ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिये सहयोग** करने पर सहमत हुए हैं।
- यह पूर्व-उद्योग सत्रों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करता है।

■ कार्य:

- ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के अलावा पेरिस समझौते में **हरपाँच वर्ष में उत्सर्जन में कटौती के लिये प्रत्येक देश के योगदान की समीक्षा करने की आवश्यकता का उल्लेख** किया गया है ताकि वे संभावित चुनौती के लिये तैयार हो सकें। वर्ष 2020 तक, देशों ने NDCs के रूप में ज्ञात जलवायु कार्रवाई के लिये अपनी योजनाएँ प्रस्तुत की थीं।
- **दीर्घकालिक रणनीतियाँ:** पेरिस समझौते के तहत दीर्घकालिक लक्ष्य की दृष्टि में उचित प्रयास करने के लिये देशों को वर्ष 2020 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु दीर्घकालिक विकास रणनीति (LT-LEDS) तैयार करने एवं प्रस्तुत करने को कहा गया है।
- दीर्घकाल में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु विकास रणनीतियाँ (LT-LEDS) NDC के लिये दीर्घकालिक क्षतिजि प्रदान करती हैं परंतु NDC की तरह वे अनिवार्य नहीं हैं।

■ प्रगति रिपोर्ट:

- पेरिस समझौते के सहयोग से देशों ने उन्नत पारदर्शी ढाँचा (ETF) स्थापित किया है। वर्ष 2024 से शुरू होने वाले ETF के तहत देश जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन उपायों और प्रदत्त या प्राप्त समर्थन से की गई कार्रवाइयों एवं प्रगति की पारदर्शी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- इसमें प्रस्तुत रिपोर्टों की समीक्षा के लिये अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं का भी प्रावधान है।
- ETF के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी वैश्विक स्टॉकटेक में उपलब्ध होगी जो दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों की दृष्टि में सामूहिक प्रगति का आकलन करेगी।

आगे की राह

- इस दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये देशों को सदी के मध्य तक जलवायु-तटस्थ विश्व निर्माण के लिये जल्द-से-जल्द ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी हेतु वैश्विक लक्ष्य रखना चाहिये।
- मध्यम अवधि के डीकार्बोनाइज़ेशन के लिये स्पष्ट मार्ग के साथ विश्वसनीय अल्पकालिक प्रतबिद्धताओं की आवश्यकता है, जो वायु प्रदूषण जैसी कई चुनौतियों को ध्यान में रखता हो, साथ ही विकास के लिये अधिक रक्षात्मक विकल्प हो सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे और यह वर्ष 2017 में लागू हुआ था।
2. समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व-औद्योगिक सत्रों से 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो।
3. विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने हेतु वर्ष 2020 से सालाना 1000 अरब डॉलर की मदद के लिये प्रतबिद्ध है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

स्रोत: डाउन टू अर्थ